

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक २० अप्रैल, २०१८

विषय:- रिस्पना नदी के पुनर्जीविरण के विस्तृत सर्वेक्षण एवं अध्ययन राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रुड़की से कराये जाने के सम्बंध में संस्था को भुगतान किये जाने वाली धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 641/प्र0अ0/नि0अनु0/रिस्पना पुनर्जीविरण दिनांक 23 फरवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रुड़की द्वारा रिस्पना नदी के पुनर्जीविरण के विस्तृत सर्वेक्षण एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना रू0 73.00 लाख+GST के सम्बंध में सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के धरोहर धनराशि के विषय में नियम-36, अग्रिम भुगतान हेतु नियम-18 एवं भारत सरकार की उक्त विशेषीकृत सचना से एकल स्रोत विषयक नियम-11 में उक्त नियमावली के नियम-71(4) के प्राविधान में छूट प्रदान करते हुए रिस्पना नदी के पुनर्जीविरण के सर्वेक्षण/अध्ययन हेतु उपलब्ध कराई गयी कार्ययोजना की धनराशि रू0 73.00 लाख (रू0 तिहत्तर लाख मात्र)+GST की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उल्लिखित संस्था को 50 प्रतिशत धनराशि रू0 36.50 लाख (रू0 छत्तीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अग्रिम भुगतान किये जाने हेतु निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने एवं अग्रिम आहरण की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) व्यय करते समय वित्त विभाग के दिशा निर्देशों एवं बजट मेनुअल एवं मितव्ययता के अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (ii) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम-18(2)(ख) नियम 71(4) के प्राविधानानुसार विशेष परिस्थितियों में परियोजना विशेष के दृष्टिगत 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की स्वीकृति दिये जाने के फलस्वरूप अग्रिम भुगतान की अन्य सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रस्तावित कार्य शीघ्र (समयसीमा) में पूर्ण किया जायेगा।
- (iii) कार्य योजना के आधार पर टाईम शेड्यूल, Deliverables आदि की सूचना संसमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (iv) स्वीकृत धनराशि का संस्था को भुगतान प्रमुख अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित संस्थायें पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगी।

- (vii) उक्त धनराशि का व्यय उक्त अध्ययन हेतु उपलब्ध करायी गयी समय सारिणी के अनुसार करके उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कृत कार्यों का विवरण निर्धारित समय सीमा के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (viii) अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों में छूट प्रकरण की तात्कालिकता एवं महत्ता को देखते हुए दी जा रही है और इसे अन्य मामलों के लिए दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।
- 2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-005-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य-03-निर्माण कार्य-00-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 05/XXVII(2)/2018, दिनांक 13 अप्रैल, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 741 (1) / 11(2)-2018-17(13)/2017तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. वित्त नियंत्रण सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. आई फाईल।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)
उप सचिव।